अर्नबका कहर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ताजा रिपोर्टके अनुसार चक्रवाती तूफान 'अर्नब' शुक्रवारको प्रात:कालसे अब समुद्रमें सक्रिय चक्रवात नहीं है, लेकिन इसके अवशेषोंसे पूर्वी और मध्य भारतमें वर्षाका दौर जारी है। २८ अक्तूबरको अर्नबने आंध्रप्रदेशके नरसापुरके निकट तट पार किया था। तटसे टकराते समय यह अत्यन्त गम्भीर चक्रवाती तूफान था और हवाओंकी अधिकतम गति लगभग १२५-१३५ किलोमीटर प्रतिघण्टा रही, जबकि झोंकोकी गति लगभग १५० किलोमीटर प्रतिघण्टातक पहुंची थी। २९ अक्तूबरको इसका अवशेष दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे लगे दक्षिण ओडिशाके ऊपर निम्न दबावके रूपमें रहा। इसके बावजूद अर्नबका प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। ओडिशा और छत्तीसगढ़में ३१ अक्तूबरतक भारीसे बहुत भारी वर्षाकी आशंका जतायी गयी है। इसके अवशेषोंकी नरमी उत्तरकी ओर पहुंचनेसे दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर भारतके कुछ हिस्सोंमें वर्षा और हिमालयी क्षेत्रोंमें बर्फबारीकी स्थिति बनी हुई है। अर्नबसे प्रभावित राज्योंमें क्षति पहुंची है, लेकिन आंध्रप्रदेश और ओडिशामें व्यापक क्षति हुई है। पानी, बिजलीकी आपूर्ति तथा ट्रेन, बस और विमान सेवाएं काफी प्रभावित हुई हैं। १५ हजारसे अधिक बिजलीके खम्भे क्षतिग्रस्त हुए हैं। काफी संख्यामें पेड़, मकान और फसलें क्षतिग्रस्त हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारकी तैयारीका स्तर काफी अच्छा रहा जिससे जन-धनकी क्षति अपेक्षाकृत कम हुई है। लाखों लोगोंको सुरक्षित स्थानोंपर ले जाया गया। अर्नबके अवशेषोंके प्रभावकी आशंका पहले ही जता दी गयी थी। इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल है। विश्वनीय रिपोर्टोंको देखते हुए कहा जा सकता है कि चक्रवात अर्नब केवल मौसमी घटना नहीं है, बल्कि भारतकी आपदा-प्रबन्धन क्षमता, तटीय अर्थव्यवस्था और जलवायु-जोखिमके सन्दर्भमें महत्वपूर्ण घटनाके रूपमें देखा जाना चाहिए। अर्नबके कारण हुई वास्तविक क्षतिका आकलन अभी होना है। खेती, बागवानी, सड़क, पुलिया, राजमार्गोंको व्यापक नुकसान हुआ है। बिजली व्यवस्थाको विशेष क्षति पहुंची है। कितने लोगोंकी मृत्यु हई है, इसका वास्तविक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। तूफानका कृषि क्षेत्रपर सबसे बड़ा आर्थिक दबाव पड़ना स्वाभाविक है। अर्नबसे कृषि-आर्थिकीपर बड़ा झटका माना जाना चाहिए। पूर्वी भारतके कई क्षेत्रोंमें वर्षाका प्रभाव बना हुआ है। चक्रवातके पश्चात् सबसे बड़ी चुनौती उत्पन्न होने वाली है। केन्द्र और राज्य सरकारोंको मिलकर इस दिशामें कार्य करना होगा। क्षतिका वास्तविक आकलन शीघ्रतासे होना चाहिए।

एटीएसकी बड़ी सफलता

उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (यूपी एटीएस) का फर्जी ई-मेल आईडी बनाने वाले नेटवर्कका पर्दाफाश करना, देशको अस्थिर करने वाली शक्तियोंपर अंकुश लगानेकी दिशामें महत्वपूर्ण सफलता मानी जायगी। इस सम्बन्धमें एटीएसने कानपुर नगरसे एक २४ वर्षीय युवकको गिरफ्तार किया है जिसके ई-मेल आईडीका इस्तेमाल नोएडा, दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम और मुम्बईमें स्कूलों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानोंको बमसे उड़ानेकी धमकी देनेके लिए किया गया था। इन धमकियोंमें सिंगर दिलजीत सिंह दोसांझके दिल्ली एनसीआरमें प्रस्तावित शो और बालीवुड अभिनेताके घरको निशाना बनानेकी धमकी भी शामिल है। खास बात यह है कि इस गिरोहके जाल पाकिस्तान, बंगलादेश समेत अन्य देशोंतक फैला है। गिरफ्तार आरोपी वर्ष २०२१ से फर्जी ई-मेल आईडी बनानेका काम कर रहा था। उसके पाससे जो लैपटाप बरामद किया गया है उसमें करीब पांच लाख ई-मेल आईडी मिले हैं, जो गम्भीर चिन्ताकी बात है। वह अपनी पहचान छिपानेके लिए वाई-फाई और प्राक्सी नेटवर्कका इस्तेमाल करता रहा। इन आईडीको सोशल मीडियाके फेसबुकसे जुड़े ग्रुप्सके जरिये बेच रहा था और बाइनेंस क्रिप्टो वालेटके जरिये भुगतान लेता था। पूछताछमें जो तथ्य सामने आये हैं वह चौंकाने वाले हैं। यह पूरा खेल अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर संचालित था। पाकिस्तान, बंगलादेश समेत तुर्किये, मिस्र और अन्य देशोंके लोगों एवं समूहोंसे सम्पर्क भी सामने आये हैं, जो देशकी शान्ति, सुरक्षाके लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि उसके मोबाइलमें आतंकी समूहोंके भी नाम हैं जिनसे धमकीभरे सन्देश भेजे गये थे। इन सबकी गहरायीसे जांच शुरू कर दी गयी है। देशविरोधी गतिविधियोंपर अंकुश लगानेके लिए यूपी एटीएसकी लगातार सक्रियता सराहनीय है। केन्द्रसे भी जानकारी साझा करनेकी जरूरत है, ताकि इन्हें समूल नष्ट किया जा सके।

लोक संवाद

राजनीतिके बदलते संकेत

महोदय,-उत्तर प्रदेशके विधान परिषद चुनावके परिणाम केवल कुछ सीटोंपर उम्मीदवारोंकी जीत और हारकी कहानी नहीं हैं, बल्कि इनके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। २०२७ के विधानसभा चुनावसे पहले आये इन नतीजोंने प्रदेशकी राजनीतिमें नये सवाल खड़े कर दिये हैं। ११ विधान परिषद सीटोंके लिए हुए चुनावमें भारतीय जनता पार्टीने छह और समाजवादी पार्टीने पांच सीटें हासिल कीं। इन परिणामोंने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेशकी राजनीतिक जमीनपर सत्तापक्ष और विपक्षके बीच मुकाबला लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। पहला निहितार्थ सत्तापक्षके लिए आत्ममंथनका है। भाजपाने छह सीटें जीतकर अपना आधार बनाये रखा लेकिन वाराणसी और लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रोंमें मिली पराजयने राजनीतिक विश्लेषणकी नयी गुंजाइश पैदा की है। विशेष रूपसे वाराणसी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीका संसदीय क्षेत्र है। यहां समाजवादी पार्टीकी सफलताको केवल एक सीटकी जीत मानकर नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। हालांकि विधान परिषदके चुनावका मतदाता वर्ग विधानसभा चुनावसे अलग होता है इसलिए इन परिणामोंको पूरे प्रदेशकी जन-भावनाका सीधा प्रतिबिंब मानना उचित नहीं होगा। दूसरा निहितार्थ विपक्षके मनोबलसे जुड़ा है। समाजवादी पार्टीने पांच सीटें जीतकर यह संकेत दिया है कि वह अपने संघटन और समर्थक वर्गके बीच सक्रिय राजनीतिक उपस्थिति बनाये हुए है। विपक्षके लिए यह परिणाम आगामी विधानसभा चुनावकी तैयारियोंको गति देनेका अवसर बन सकता है। लेकिन विधान परिषदमें मिली सफलताको विधानसभा चुनावमें जीतकी गारंटी समझना भी राजनीतिक भूल होगी। तीसरा निहितार्थ शिक्षकों और स्नातकोंके मुद्दोंसे संबंधित है। विधान परिषदकी इन सीटोंपर शिक्षक और स्नातक मतदाता अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। शिक्षाकी गुणवत्ता शिक्षकोंकी समस्याएं रोजगारके अवसर विश्वविद्यालयोंकी स्थिति और युवाओंके भविष्य जैसे मुद्दे इस चुनावके व्यापक संदर्भका हिस्सा हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियोंके सामने अब चुनौती होगी कि वे इन वर्गोंकी अपेक्षाओंको सदनमें प्रभावी ढंगसे उठायें। चौथा निहितार्थ संघटनात्मक क्षमता और स्थानीय नेतृत्वसे जुड़ा है। चुनाव परिणाम बताते हैं कि स्थानीय स्तरपर उम्मीदवारोंकी स्वीकार्यता संघटनकी सक्रियता और मतदाताओंसे संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल बड़े नेताओंके प्रभावके भरोसे चुनावी सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। राजनीतिक दलोंको स्थानीय समस्याओं और मतदाताओंकी अपेक्षाओंको समझना होगा। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ २०२७ के विधानसभा चुनावकी रणनीतिसे जुड़ा है। इन नतीजोंसे भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनोंको अपनी राजनीतिक तैयारियोंकी समीक्षा करनेका अवसर मिला है। भाजपाके सामने अपने समर्थन आधारको मजबूत बनाये रखनेकी चुनौती है जबकि समाजवादी पार्टीके सामने इस सफलताको व्यापक जनसंपर्क और संघटनात्मक मजबूतीमें बदलनेका प्रश्न है। अंततः एमएलसी चुनावके नतीजोंको न तो सत्तापक्षके लिए अंतिम चेतावनी मानना चाहिए और न ही विपक्षके लिए आगामी विजयका प्रमाण। लोकतंत्रमें प्रत्येक चुनाव अपने साथ कुछ संदेश लेकर आता है। इन संदेशोंको समझनेके लिए आंकड़ोंके साथ मतदाता वर्ग स्थानीय परिस्थितियों और जनहितके मुद्दोंका भी विश्लेषण आवश्यक है। उत्तर प्रदेशकी राजनीतिमें इन परिणामोंका वास्तविक महत्व इस बातसे तय होगा कि राजनीतिक दल जनताकी अपेक्षाओंको कितनी गम्भीरतासे समझते हैं और उन्हें पूरा करनेके लिए क्या कदम उठाते हैं। **-सूर्यदीप कुशवाहा, वाराणसी।**

ट्रम्पसे असंतुष्ट अमेरिकी मतदाता

लगभग ६८ प्रतिशत मतदाता ट्रम्पके कामकाजसे और ७१ प्रतिशत उनकी आर्थिक नीतियोंसे असंतुष्ट हैं। युवा वर्ग और विभिन्न जातीय अल्पसंख्यकोंमें ट्रम्पके प्रति कड़ी नाराजगी देखी गयी है। अमेरिकाका मध्यवर्ग पेट्रोलियम पदार्थों, गैस, भोजन और जीवनयापनकी बढ़ती लागतको लेकर ट्रम्पको कोसना शुरू कर चुका है।

❐ पुष्परंजन

अमेरिकी मध्यावधि चुनावका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदान ३ नवंबरको है। ट्रम्प मध्यावधि चुनाव हार भी जाते हैं, फिर भी उनकी कुर्सी आसानीसे नहीं जायगी। ट्रम्पने खुद आशंका जतायी है कि यदि डेमोक्रेट्स कांग्रेसपर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो वे उनपर महाभियोग चलानेकी कोशिश कर सकते हैं। यदि डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा या सीनेटमें बहुमत पा लेती है तो ट्रम्पके लिए बजट या नीतियां पास कराना बेहद मुश्किल हो जायगा। हालांकि उनके पास वीटोकी शक्ति होगी, जिसका इस्तेमाल वे किसी भी बिलको रोकनेके लिए कर सकते हैं। बहुमत खोनेकी स्थितिमें विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रम्प प्रशासनकी नीतियोंकी संसदीय जांच शुरू कर सकती है, जिससे उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज भी ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदायके लगभग ७० प्रतिशतसे अधिक मतदाता डोनाल्ड ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टीका खुलकर समर्थन करते हैं। इनका मिजाज बदलता नहीं दिख रहा। लेकिन जो बदल रहे हैं, वे हैं ब्लैक, हिस्पैनिक, यहूदी, मुस्लिम, ह्वाइट वर्किंग-क्लास और इवेंजेलिकल मतदाता। २०२४ में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुननेमें इनका बड़ा योगदान था। स्विचर वोटर्सका अब ट्रम्प प्रशासनसे मोहभंग हुआ है। ट्रम्प अमूमन अमेरिका फर्स्ट और नेशनल इंटरेस्ट जैसे शब्द इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जब परिवारके बजटपर दबाव पड़ता है तो ये टोटके बकवास लगने लगते हैं।



भारत-अमेरिका व्यापार संधिको ट्रम्प प्रशासनने अत्यधिक जटिल बना रखा है। ट्रम्प प्रशासनकी ओरसे समय-समयपर टैरिफ दरों और शर्तोंमें बदलावसे दोनों पक्षोंके बीच भरोसा कायम करनेमें चुनौतियां आयी हैं। अब ट्रम्प मध्यावधि चुनावमें जीतें या हारें, उससे पीएम मोदीको क्या करना है, बल्कि ट्रम्प यदि हारते हैं तो मोदीपर उनके प्रहारकी धार कम हो जायगी। २०२० में ट्रम्पकी जीतके लिए भारतमें विशेष पूजा-अर्चना, हवन और महायज्ञ किये गये थे। सवाल है अब ये हिन्दू संघटन ट्रम्पके लिए पूजा-पाठ, हवन इत्यादि क्यों नहीं करवा रहे।

ट्रम्प यदि मध्यावधि चुनाव जीत गये, तब तो मानकर चलिये, तेहरानकी खैर नहीं होगी। अगले दो वर्षोंतक ट्रम्प ईरान जैसे कुछ और युद्ध वाले इलाके सृजित कर लेंगे। सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टीका संसदके दोनों सदनों (प्रतिनिधि सभा और सीनेट) पर नियंत्रण बना रहेगा, जिससे ट्रम्प अपने एजेंडे, टैक्स सुधारों और नीतियोंको आसानीसे आगे बढ़ा सकेंगे। ट्रम्पपर महाभियोग चलाने की संभावना काफी कम हो जायगी। जीत गये तो वादेके अनुसार २७ करोड़ १५ लाख अमेरिकी वयस्कोंको ५,००० डालरका चेक देना पड़ेगा। इससे सरकारी खजानेपर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। हालिया सर्वेक्षणोंपर यकीन करें तो लगभग ८७ प्रतिशत डेमोक्रेटिक मतदाता ट्रम्पके कामकाज और उनकी आर्थिक नीतियोंसे असंतुष्ट हैं। करीब ७२ प्रतिशत अश्वेत मतदाता ट्रम्पके कुल कामकाजको नापसंद करते हैं। राष्ट्रीय स्तरपर स्वतंत्र मतदाताओंका एक बड़ा हिस्सा ट्रम्पसे निराश है। लगभग ६८ प्रतिशत स्वतंत्र मतदाता ट्रम्पके कामकाजसे और ७१ प्रतिशत उनकी आर्थिक नीतियोंसे असंतुष्ट हैं। जेन-जी श्रेणीके युवा वर्ग और विभिन्न जातीय अल्पसंख्यकोंमें ट्रम्पके प्रति कड़ी नाराजगी देखी गयी है। अमेरिकाका मध्यवर्ग पेट्रोलियम पदार्थों, गैस, भोजन और जीवनयापनकी बढ़ती लागतको लेकर ट्रम्पको कोसना शुरू कर चुका है। एशियाई अमेरिकी और पैसिफिक आइलैंडर (एएपीआई) मतदाता अमेरिकी मतदाताओंके सबसे विविध समूहोंमेंसे एक हैं। 'आपी' मतदाताओंका वर्ग सबसे तेजीसे बढ़ रहा है। एएपीआई (आपी) समुदायमें लगभग १.७ करोड़ योग्य मतदाता हैं, जिनमेंसे ५६ प्रतिशतने २०२४ में अपना वोट डाला था। द एसोसिएटेड प्रेस-नॉर्क सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च (एपी-नॉर्क-एएपीआई) के एक नये पोलके अनुसार ३ नवंबरके मध्यावधि चुनावोंके करीब आते-आते एशियाई अमेरिकी, मूल हवाईयन और प्रशांत द्वीपवासी रिपब्लिकन पार्टीसे और अधिक निराश हो गये हैं। एपी-नॉर्क-एएपीआई द्वारा ८ से १५ सितंबर २०२६ के बीच किये गये सर्वेक्षणसे पता चलता है कि ट्रम्पके दूसरे कार्यकालके दौरान अर्थव्यवस्थाको लेकर उनकी छवि खराब हुई है। इन वयस्कोंमेंसे लगभग एक-चौथाई लोग ही राष्ट्रपतिके रूपमें ट्रम्पके कामकाजके तरीकेको पसंद करते हैं। अर्थव्यवस्थाके मोर्चेपर उनके प्रदर्शनको केवल दस मेंसे दो लोग ही सही मानते हैं, जबकि एएपीआई समूहके अधिकांश वयस्क इसे आगामी चुनावके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दोंमेंसे एक मानते हैं। आयोवाके कॉर्निंगमें रहने वाली ४५ वर्षीय कोरियाई अमेरिकी रेबेका लारोकोने २०१६ में ट्रम्पको वोट दिया था, लेकिन अर्थव्यवस्थाको संभालनेके उनके तरीकेको लेकर आश्वस्त नहीं हैं, खासकर ऐसे समयमें जब ईरान युद्धके कारण पेट्रोल-डीजलकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले तीन प्रेसिडेंशियल साइकिलमें लगभग ६,२०,००० नये मतदाता बने, जिनमें कैलिफोर्निया, हवाई, इलिनोइस, मैसाचुसेट्स, मिनेसोटा, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, नेवादा, ओरेगन, वर्जीनिया, टेक्सास और वाशिंगटन जैसे राज्योंमें इनकी ताकत बढ़ी या यूं कहें कि पांच फीसदी नये आपी मतदाता नयी ताकत बने। ट्रम्पने शुरूमें अपने स्तरपर कुछ प्रमुख पदोंपर आपी समूहके व्यक्तियों (जैसे-तुलसी गबार्ड, काश पटेल) को नियुक्त किया था। लेकिन यह बहुत टिकाऊ साबित नहीं हुआ। तुलसी गबार्डने स्वयं २२ मई, २०२६ को राष्ट्रीय खुफिया निदेशकके पदसे इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफेकी मुख्य वजह अपने पति अब्राहम विलियम्सका बोन कैंसरसे पीड़ित होना बतायी थी, जिसके चलते वह अपने परिवारके साथ रहना चाहती थीं। रिपोर्टोंमें यह भी कहा गया था कि ईरान नीति और विदेशी मामलोंपर उनके डोनाल्ड ट्रम्पसे मतभेद थे और उन्हें बड़े फैसलोंसे दरकिनार किया जा रहा था। काश पटेल अब भी एफबीआईके निदेशकके पदपर बने हुए हैं। हालांकि अप्रैल २०२६ में उनकी कार्यशैली, शराबकी लत और अनुपस्थितिको लेकर द अटलांटिककी एक रिपोर्टके बाद उनके इस्तीफे या हटाये जानेकी अटकलें जरूर तेज हुई थीं। फिर भी, काश पटेलको ट्रम्पने लो-प्रोफाइलमें रखा है। यह जगजाहिर है कि ट्रम्प और प्रधान मंत्री मोदीके 'माई डियर फ्रेंड' वाले रिश्ते सहज नहीं रहे। २२ सितंबर २०१९ को ह्यूस्टनके एनआरजी स्टेडियममें आयोजित 'हाउडी मोदी' जैसे मेगा इवेंटका इतिहास दोहराया नहीं जा सका। रूससे लगातार कच्चा तेल खरीदना भी दोनों नेताओंके बीच अनबनकी एक बड़ी वजह बनी। भारत-पाकिस्तानके बीच युद्धविराम करानेकी दावेदारी और एपस्टीन फाइल्स जैसे विवादित विषयोंको उठाकर ट्रम्प प्रधान मंत्री मोदीपर मानसिक दबाव बनाते रहे। भारत-अमेरिका व्यापार संधिको ट्रम्प प्रशासनने अत्यधिक जटिल बना रखा है। ट्रम्प प्रशासनकी ओरसे समय-समयपर टैरिफ दरों और शर्तोंमें बदलाव (जैसे-दस प्रतिशत, १५ प्रतिशत, १९ प्रतिशत या २५ प्रतिशत तकके जवाबी शुल्कका मुद्दा) से दोनों पक्षोंके बीच भरोसा कायम करनेमें चुनौतियां आयी हैं। अब ट्रम्प मध्यावधि चुनावमें जीतें या हारें, उससे पीएम मोदीको क्या करना है, बल्कि ट्रम्प यदि हारते हैं तो मोदीपर उनके प्रहारकी धार कम हो जायगी। आप २०२० का मंजर याद कीजिए। ट्रम्पकी जीतके लिए भारतमें पुजारियों और हिन्दू समूहों द्वारा विशेष पूजा-अर्चना, हवन और महायज्ञ किये गये थे। सवाल है अब ये हिन्दू संघटन ट्रम्पके लिए पूजा-पाठ, हवन इत्यादि क्यों नहीं करवा रहे।

संघटनात्मक आत्ममंथनका अवसर

बैलेट पेपरसे चुनाव करानेपर मतदानका माध्यम बदला, लेकिन लोकतंत्रकी मूल कसौटियां नहीं बदलीं। मतदाता का विश्वास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी मतगणना और परिणामोंकी विश्वसनीयता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

❐ महेन्द्र तिवारी

पिछले कुछ समयसे इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनोंकी विश्वसनीयताको लेकर राजनीतिक बहस चल रही है। विपक्षके कई नेता बैलेट पेपरसे चुनाव करानेकी मांग करते रहे हैं। ऐसेमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटकमें विधान परिषदकी २८ सीटोंके लिए बैलेट पेपरसे हुए चुनावोंने एक बार फिर इस बहसको तेज कर दिया है। सवाल यह है कि बैलेट पेपरसे चुनाव करानेपर आखिर क्या बदला। क्या इससे चुनावी व्यवस्थाकी विश्वसनीयता साबित हुई। २३ अक्तूबर २०२६ को चार राज्योंमें विधान परिषदकी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रोंकी सीटोंके लिए मतदान हुआ। इन चुनावोंमें इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनोंके स्थानपर मतपत्रोंका इस्तेमाल किया गया। मतगणनाके दौरान भाजपा और उसके सहयोगियोंने कई सीटोंपर सफलता प्राप्त की। सपाने उत्तर प्रदेशमें अपनी उपस्थिति मजबूत की, जबकि बिहारमें जन सुराज पार्टीने भी विधान परिषदमें अपना खाता खोला। कांग्रेसको शुरुआती परिणामोंमें किसी सीटपर सफलता नहीं मिली। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने इसी स्थितिका उल्लेख करते हुए कांग्रेसपर राजनीतिक टिप्पणी की और सवाल किया कि बैलेट पेपरसे हुए चुनावोंमें पार्टी कितनी सीटें जीत पायी। इस टिप्पणीने मतदान प्रणालीको लेकर चल रही बहसको फिर चर्चामें ला दिया।

हालांकि अंतिम परिणामोंने इस राजनीतिक चर्चाको एक नया मोड़ दिया। महाराष्ट्रके नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्रमें कांग्रेसके अभिजीत वंजारीने भाजपाके सुधाकर कोहलेको ३२७१ मतोंसे पराजित कर दिया। इस सीटपर मतगणना लम्बी चली और दूसरी वरीयताके मतोंकी गणनाके बाद परिणाम सामने आया। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका मुख्यालय होनेके साथ महाराष्ट्रके मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरीका गृहक्षेत्र भी है। ऐसे क्षेत्रमें कांग्रेसकी जीतने भाजपाके लिए राजनीतिक चुनौती खड़ी की। इससे स्पष्ट होता है कि चुनावके शुरुआती रुझानों और अंतिम परिणामोंमें अन्तर हो सकता है। इन चुनावोंसे पहला बदलाव मतदानके तरीकेमें दिखाई दिया। इलेक्ट्रॉनिक मशीनोंके स्थानपर मतपत्रोंका उपयोग किया गया। लेकिन केवल मतदानका माध्यम बदलनेसे मतदाताओंकी राजनीतिक पसंद नहीं बदल जाती। मतदाता किसी उम्मीदवारको उसकी लोकप्रियता, राजनीतिक विचारधारा, स्थानीय कामकाज, संघटनकी सक्रियता और अपनी समस्याओंके समाधानकी उम्मीदके आधारपर चुनते हैं। इस दृष्टिसे बैलेट पेपरसे हुए चुनावोंने यह नहीं बताया कि कौन-सी मतदान प्रणाली राजनीतिक दलोंको अधिक सीटें दिलाती है। उन्होंने केवल यह दिखाया कि मतपत्रोंसे मतदान होनेपर भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और उम्मीदवारोंकी क्षमता महत्वपूर्ण बने रहते हैं। दूसरा बदलाव राजनीतिक बहसमें दिखाई दिया। विपक्ष लम्बे समयसे इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनोंकी विश्वसनीयतापर सवाल उठाता रहा है। ऐसेमें बैलेट पेपरसे हुए चुनावोंके परिणामोंको भाजपाने विपक्षकी दलीलोंके जवाबके रूपमें प्रस्तुत किया। उसका तर्क रहा कि जब मतपत्रोंसे चुनाव हुए, तब भी कांग्रेसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर विपक्ष यह कह सकता है कि विधान परिषदके सीमित निर्वाचन क्षेत्रोंके परिणामोंकी तुलना लोकसभा और विधानसभा चुनावोंसे सीधे नहीं की जा सकती। दोनों पक्षोंकी दलीलोंको समझते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी राजनीतिक दलकी हार अपने आपमें मतदान प्रणालीमें गड़बड़ी या उसकी पूर्ण निष्पक्षताका प्रमाण नहीं होती। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष विधान परिषदके चुनावोंका स्वरूप है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रोंमें सामान्य मतदाताओंके बजाय निर्धारित पात्रता वाले मतदाता मतदान करते हैं। इन क्षेत्रोंमें शिक्षकों, शिक्षाविदों और पंजीकृत स्नातकोंकी समस्याएं चुनावी निर्णयको प्रभावित करती हैं। इसलिए इन चुनावोंको पूरे देशके मतदाताओंकी राजनीतिक पसंदका प्रतिनिधि मानना उचित नहीं होगा। लोकसभा चुनावोंमें मतदाताओंका दायरा कहीं अधिक व्यापक होता है और राष्ट्रीय नेतृत्व, महंगी, रोजगार, कृषि, सुरक्षा तथा शासन जैसे मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या बैलेट पेपरसे चुनाव करानेपर चुनावी पारदर्शिता बढ़ जाती है। इसका उत्तर केवल चुनाव परिणाम देखकर नहीं दिया जा सकता। मतपत्रोंके माध्यमसे मतदानमें मतदाता अपनी पसन्द कागजपर दर्ज करता है। इससे मतोंकी भौतिक जांचकी सुविधा मिल सकती है, लेकिन मतपत्रोंकी छपाई, सुरक्षित परिवहन, भंडारण, मतगणना और अमान्य मतोंका निर्धारण जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनोंमें तकनीकी सुरक्षा, निर्धारित जांच, सुरक्षित रखरखाव और प्रक्रियाकी निगरानी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी प्रणालीकी विश्वसनीयता उसके सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और शिकायतोंके निष्पक्ष निवारणपर निर्भर करती है। निष्पक्ष चुनावके लिए मतदाता सूचीकी शुद्धता, उम्मीदवारोंको समान अवसर, मतदान केन्द्रोंकी व्यवस्था, मतदाताओंकी स्वतंत्रता, चुनाव अधिकारियोंकी निष्पक्षता और मतगणनाकी विश्वसनीयता भी आवश्यक हैं। यदि इन पहलुओंमें कोई कमी हो तो केवल बैलेट पेपर अपना आपमें हर समस्याका समाधान नहीं बन सकता। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनोंके इस्तेमाल मात्रसे हर चुनाव स्वत: निष्पक्ष सिद्ध नहीं हो जाता। किसी भी आरोपका निर्णय राजनीतिक बयानबाजीके बजाय प्रमाणों और निर्धारित जांच प्रक्रियाके आधारपर होना चाहिए। कांग्रेसके लिए इन चुनावोंका परिणाम संघटनात्मक आत्ममंथनका अवसर है। पार्टीको यह समझना होगा कि केवल मतदान प्रणालीपर सवाल उठानेसे मतदाताओंका समर्थन प्राप्त नहीं होता। स्थानीय नेतृत्व, प्रभावी उम्मीदवारोंका चयन, कार्यकर्ताओंकी सक्रियता और जनतासे नियमित संवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अंतत: बैलेट पेपरसे चुनाव करानेपर मतदानका माध्यम बदला, लेकिन लोकतंत्रकी मूल कसौटियां नहीं बदलीं। मतदाताका विश्वास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी मतगणना और परिणामोंकी विश्वसनीयता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। नागपुरमें कांग्रेसकी जीत यह भी बताती है कि शुरुआती रुझान अंतिम निर्णय नहीं होते और चुनावी मुकाबलेमें अंतिम मतगणनातक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि बैलेट पेपरसे चुनाव करानेपर किस दलको कितनी सीटें मिलीं, बल्कि यह है कि क्या चुनाव प्रक्रियापर जनताका विश्वास मजबूत हुआ। लोकतंत्रकी सफलता किसी एक दलकी जीत या हारसे नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थासे तय होती है जिसमें प्रत्येक मतदाताका मत सुरक्षित रहे, हर शिकायतकी निष्पक्ष जांच हो और राजनीतिक दल प्रमाणोंका सम्मान करते हुए जनताके निर्णयको स्वीकार करें। मतदानका माध्यम चाहे कोई भी हो, लोकतंत्रकी वास्तविक जीत तभी होगी जब चुनाव निष्पक्ष हों और जनताका विश्वास कायम रहे।



प्रेम भावसे प्रार्थना

❐ ओशो

प्रेम यदि पाप है तो पुण्य असंभव है। क्योंकि पुण्यका सार प्रेमके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तथाकथित साधु, महात्मा यही कहते हैं कि प्रेम पाप है और वह ऐसी व्यर्थकी बात कहते रहे हैं, लेकिन इन्होंने इतने लंबे अरसेसे कही है कि उसकी व्यर्थता, उसका विरोधाभास दिखाई नहीं पड़ता। प्रेमको तो वह पाप कहते हैं और प्रार्थनाको पुण्य कहते हैं और तुमने कभी गौरसे नहीं देखा कि यदि प्रेम पाप है तो प्रार्थना भी पाप हो जायगी। क्योंकि प्रार्थना प्रेमका ही परिशुद्ध रूप है। माना कि प्रेममें कुछ अशुद्धियां हैं, लेकिन पाप नहीं है। सोना यदि अशुद्ध हो तो भी लोहा नहीं है। सोना अशुद्ध हो तो भी सोना है। अशुद्ध होकर भी सोना, सोना है। रही शुद्ध करनेकी बात, सो शुद्ध कर लेंगे। कूड़े, कर्कटको जला देंगे, सोनेको आगसे गुजार लेंगे, जो व्यर्थ है जल जायगा आगमें, जो सार है, जो शुद्ध है बच जायगा। प्रेम और प्रार्थनामें उतना ही फर्क है जितना अशुद्ध सोने और शुद्ध सोनेमें। परन्तु दोनों ही सोना हैं। अतीतने प्रार्थना और प्रेमको अलग-अलग तोड़ दिया था और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रेम कलुषित हो गया। एक तरफ प्रेमको अपराध बना दिया तो जो प्रेममें थे, उनकी आत्माका अपमान किया, उनके भीतर आत्मनिंदा पैदा कर दी और इस जगतमें इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं है कि किसी व्यक्तिके भीतर आत्मनिंदा पैदा हो जाय। प्रेम पाप है तो जो भी प्रेम करते हैं, सब पापी हैं और कौन है जो प्रेम नहीं करता। कोई पत्नीको करता है, कोई पतिको, कोई बेटेको, कोई भाईको, कोई मित्रको। शिष्य भी तो गुरुको प्रेम करते हैं! गुरु भी शिष्योंको प्रेम करता है! यहां जितने संबंध हैं, वह सारे संबंध मात्र प्रेमके हैं। हमने प्रेमको पापी कर दिया। सारा संसार हमने पापसे भर दिया, एक छोटी-सी भूल करके कि प्रेम पाप है। दूसरा दुष्परिणाम हुआ है कि जब प्रेम पाप हो गया तो प्रार्थना हमारी थोथी हो गयी, उसमें प्राण न रहे, औपचारिक हो गयी। प्राण तो प्रेमसे मिल सकते थे तो प्रेमको तो हमने पाप कह दिया। जीवन तो प्रेमसे मिलता है। प्रार्थनाके द्वार बंद कर दिये। प्रेमकी ही भूमिसे प्रार्थना रस पाती है तो हमने भूमिको निंदित कर दिया और प्रार्थनाके वृक्षको भूमिसे अलग कर लिया। भूमि वृक्षहीन हो गयी और वृक्ष मुर्दा हो गया। मैं घोषणा करता हूं कि प्रेम पुण्य है। विरहकी अग्निसे गुजारो इसे और तुम धीरे-धीरे पाओगे कि तुम्हारे हाथोंमें प्रार्थनाका पक्षी लग गया है, जिसके पंख हैं, जो आकाशमें उड़ सकता है। जो इतना हल्का है! क्योंकि सारा बोझ कट गया, सारी व्यर्थता गिर गयी। जिस दिन प्रार्थनाको अनुभव कर पाओगे, उस दिन तुम धन्यवाद दोगे अपने सारे प्रेमके संबंधोंको, क्योंकि उनके बिना तुम प्रार्थनातक कभी नहीं आ सकते थे। प्रेम जब प्रार्थना बनता है तो परमात्माके द्वार ख